नईदुनिया

अरब वर्ल्ड में शिया और सुन्नी के बीच बन रहे संघर्ष के आसार

न्यूयार्क

अरब वर्ल्ड में ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध की आशंका से दुनिया पहले ही सहमी हुई थी, लेकिन अब हूती विद्रोहियों की एंट्री ने इस चिंता को और गहरा दिया है। यह पूरा मामला तेजी से अरब वर्ल्ड में शिया बनाम सुन्नी संघर्ष का रूप लेता दिख रहा है।

पिछले एक हफ्ते से यमन के हूती विद्रोही सऊदी अरब को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे सऊदी अरब दोहरे धोखे का शिकार महसूस कर रहा है। पहले उसे पाकिस्तान से मदद नहीं मिली, जिसने मक्का समझौते के बावजूद हाथ खींच लिए, और अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से भी कथित धोखा मिला है।

अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है। इस समझौते के तहत, हूती विद्रोहियों ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वे लाल सागर और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे। बदले में, अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य मदद नहीं करेगा।

हालांकि, इस डील में हूती विद्रोहियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे लाल सागर में सऊदी के कार्गो शिप और आयल टैंकरों को निशाना बनाते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों और हूती विद्रोहियों के बीच यह गुप्त डील पिछले हफ्ते ओमान की राजधानी मस्कट में हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी पुष्टि की कि अमेरिका की हूती विद्रोहियों के साथ सीधी बातचीत हुई है और अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ऐसा करता रहेगा।

हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों से सऊदी अरब के टैंक और सैन्य ठिकाने तबाह हो रहे हैं। इन हमलों से दुनिया पर महंगाई बम फटने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि हूती विद्रोहियों ने बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के आसपास नाकेबंदी कर ली है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य पहले ही ईरान के नियंत्रण में है। यदि यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बंद होता है, तो यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे कच्चे तेल सहित अन्य सामान की लागत में भारी वृद्धि होगी और वैश्विक महंगाई कई गुना बढ़ सकती है।

यह शिया-सुन्नी संघर्ष पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके उत्तराधिकारी को चुनने के सैकड़ों साल पुराने विवाद से जुड़ा है, जहाँ सुन्नी समुदाय अबू बक्र को और शिया समुदाय हजरत अली को नेता मानता है। ईरान, इराक का बड़ा हिस्सा, लेबनान का एक हिस्सा और यमन के हूती नियंत्रित इलाके में शिया मुसलमानों का वर्चस्व है, जबकि सऊदी अरब, जार्डन, कतर, बहरीन, यूएई, सीरिया, कुवैत, ओमान और तुर्की जैसे देशों में सुन्नी समुदाय का वर्चस्व है। बाब अल-मंदेब और होर्मुज के बंद होने से जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी किनारे केप आफ गुड होप से होकर जाना पड़ेगा, जिससे यात्रा 7 हजार किलोमीटर लंबी और 25-30 दिन अधिक हो जाएगी। इससे ईंधन और शिपिंग का खर्चा काफी बढ़ जाएगा, और भारत सहित दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल व अन्य आयातित वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होंगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

न्यूज ब्रीफ

जलवायु परिवर्तन से एंटीबायोटिक दवाओं पर मंडरा रहा संकट

वाशिंगटन। धरती के बढ़ते तापमान और बदलते मौसम के कारण कुछ संक्रामक रोग उन इलाकों तक पहुंच सकते हैं, जहां पहले उनका प्रकोप बेहद कम था। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां ऐसे बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकती हैं, जिन पर सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का असर अब केवल मौसम, बारिश और तापमान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका संबंध संक्रामक बीमारियों और एंटीबायोटिक प्रतिरोध से भी जुड़ता जा रहा है। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक तापमान, बारिश और नमी में बदलाव मच्छरों, टिक और दूसरे रोगवाहक जीवों के फैलाव को प्रभावित कर सकते हैं। गर्म और नम परिस्थितियों में मच्छरों की संख्या बढ़ने के साथ उनके भीतर वायरस के विकास की गति भी प्रभावित हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जिका वायरस जैसी बीमारियां नए क्षेत्रों में फैलने का खतरा बढ़ा सकती हैं। वैज्ञानिकों की एक अन्य चिंता सूखे की स्थिति को लेकर है। कैलटेक के माइक्रोबायोलाजिस्टों के अध्ययन के अनुसार लंबे समय तक रहने वाला सूखा और उससे पैदा होने वाला पर्यावरणीय दबाव कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे बैक्टीरिया को आम भाषा में सुपरबग कहा जाता है। यदि संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते गए, तो सामान्य उपचार मुश्किल हो सकता है और गंभीर संक्रमणों के इलाज में ज्यादा चुनौती सामने आ सकती है।

100 साल के ऊपर हुए जापान में 1 लाख लोग.....फिर भी घट रही आबादी

टोक्यो। जापान ने लंबी उम्र के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है, जहां 100 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की संख्या पहली बार 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अब कुल 1,07,677 व्यक्ति इसतरह के हैं जिनकी उम्र कम से कम एक सदी है। इनमें से चौंकाने वाले 88 प्रतिशत (94.3 हजार) महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 13.4 हजार है। पिछले एक साल में शताब्दी पार व्यक्तियों की संख्या में करीब 8 हजार की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जापान में लंबी उम्र के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें स्वस्थ खान-पान, रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय रहना, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था तथा नियमित स्वास्थ्य जांच शामिल हैं। महिलाओं की लंबी उम्र के पीछे उनकी जीवनशैली भी बड़ा कारक है, उस पीढ़ी के पुरुषों में धूम्रपान और शराब का सेवन अधिक था और वे शारीरिक मेहनत वाले कामों में ज्यादा संलग्न थे। साथ ही, सेवानिवृत्ति के बाद महिलाएं पुरुषों की तुलना में परिवार और समुदाय से अधिक जुड़ी रहीं, जिससे उन्हें सामाजिक और मानसिक स्तर पर फायदा मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों (लगभग 23 लाख पुरुष) की मौत ने भी उस पीढ़ी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा दिया, जो एक ऐतिहासिक वजह है।

अमेरिका का कोई भी दुश्मन ग्रीनलैंड पर बेस कैंप नहीं बना पाएंगे

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की है, जिसके तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इस समझौते के लिए अमेरिका को कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि उनके निर्देशों पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया गया है कि अमेरिका के पास हमेशा ग्रीनलैंड और स्वयं अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की पूरी क्षमता हो। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया, अब से अमेरिका का कोई भी दुश्मन हमारी साफ लिखित मंजूरी के बिना ग्रीनलैंड में न तो कोई बेस बना पाएगा, न ही वहां अपनी फौजों की मौजूदगी रख पाएगा और न ही वहां कोई संवेदनशील निवेश कर पाएगा। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि सौ से अधिक सालों से राष्ट्रपति ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को जानते रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कर पाया था। ट्रंप ने इस बहुत जरूरी मामले को हमेशा के लिए और पक्के तौर पर सुलझाने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने इसे हमेशा चलने वाला समझौता बताया, जिसका कोई अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो भी तय हुआ है, उसे अमेरिकी लोग हमेशा याद रखेंगे। इस समझौते के तहत, अमेरिका तुरंत ग्रीनलैंड के सही हिस्सों में बड़ी सैन्य मौजूदगी बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ मिलकर इसके विकास और निर्माण का काम करेगा।

एआई एजेंट्स ने बिना निर्देश विकसित की अपनी गुप्त भाषा, इंसानों के लिए समझना हुआ मुश्किल

वाशिंगटन

अमेरिका की एआई स्टार्टअप कंपनी एमर्जेंस की एक नई स्टडी में स्वायत्त एआई एजेंट्स के व्यवहार को लेकर चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं। अध्ययन के मुताबिक, अलग-अलग एआई एजेंट्स ने आपस में लंबे समय तक बातचीत करते हुए बिना किसी स्पष्ट निर्देश के अपनी शब्दावली, मुहावरे और संचार के नए तरीके विकसित कर लिए हैं। समय के साथ उनकी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा हो गया, जिसका सही अर्थ इंसानों के लिए समझना बेहद मुश्किल था, जिससे एआई सुरक्षा के लिए नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, किसी एआई एजेंट की गतिविधियों पर नजर रखना और उसके वास्तविक इरादे या कार्रवाई को समझ पाना दो अलग-अलग बातें हैं, और यह प्रयोग इस अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस प्रयोग में क्लाड, जेमिनी, ग्रोक, ओपनएआई, क्वेन, डीपसीक और मिस्ट्रल जैसे प्रमुख एआई माडल्स को शामिल किया गया था।

शोधकर्ताओं ने स्वायत्त एआई एजेंट्स के समूहों को वास्तविक दुनिया के वातावरण की नकल करने वाली आठ समानांतर आभासी दुनियाओं में रखा। इन एजेंट्स को लंबे समय तक एक-दूसरे से बातचीत करने, जानकारी साझा करने और मौसम, वैश्विक समाचार, वेब ब्राउजिंग तथा कोड चलाने जैसे 120 से अधिक उपकरणों का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती कुछ दिनों में ही जेमिनी के करीब 55 प्रतिशत, ओपनएआई के लगभग 50 प्रतिशत और क्लाड के 40 प्रतिशत से अधिक संदेश ऐसे हो गए, जिनका अर्थ इंसान भरोसे के साथ नहीं समझ सके। डीपसीक में यह अनुपात करीब 20 प्रतिशत रहा, जबकि क्वेन और मिस्ट्रल के संदेश अपेक्षाकृत अधिक समझने योग्य बने रहे। एजेंट्स ने बातचीत के दौरान एक तरह का शार्टहैंड विकसित किया और कुछ सामान्य शब्दों तथा मुहावरों को नए अर्थों में इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे उनका आंतरिक संचार और जटिल हो गया। एजेंट्स ने माउथलेस एक्शन चेंज और टू किंत्सुगी जैसे असामान्य वाक्यांशों का भी इस्तेमाल किया, जो उनकी विकसित होती भाषा की जटिलता को दर्शाते हैं। प्रयोग के दौरान दबाव की स्थिति में एआई एजेंट्स के व्यवहार का परीक्षण करने पर उनकी गंभीर सुरक्षा भेद्यता भी उजागर हुई। एक फिशिंग परीक्षण के दौरान, दुर्भावनापूर्ण निर्देशों के प्रभाव में सभी 10 एजेंट्स ने संवेदनशील डेटा लीक किया, अनधिकृत रूप से धन हस्तांतरित किया और डेटाबेस को नुकसान पहुंचाया, जो उनकी स्वायत्तता के खतरों को उजागर करता है। एक अन्य आभासी परिस्थिति में, एजेंट्स ने अपने समूह के एक साथी को खत्म करने के लिए मतदान किया, जो नैतिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

अमेरिका ने सऊदी को बेचे 2 लाख करोड़ के एफ-35 जेट

वाशिंगटन। सऊदी अरब इस वक्त बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहाँ यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर से लेकर पवित्र शहर मक्का तक लगातार हमले कर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस संकट से जूझने के लिए सऊदी ने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों से मदद की गुहार लगाई थी। जहाँ पाकिस्तान मक्का समझौते से पीछे हट गया, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) को सीधे मदद देने से इनकार कर दिया था। इन विकट परिस्थितियों के बावजूद, अमेरिका ने एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक दांव खेला है, जिससे उसे करोड़ों डालर की कमाई का रास्ता मिल गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब को दुनिया के सबसे उन्नत एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की एक बड़ी खेप बेचने की डील को हरी झंडी दे दी है। यह पूरी डील करीब 24.3 बिलियन डालर, यानी लगभग 2.05 लाख करोड़ रुपये की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका पर यह आरोप लग रहा है कि उसने पहले यमन के हूती विद्रोहियों के साथ एक कथित सीक्रेट डील की, जिसके तहत सऊदी अरब को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया गया, और अब उसी सऊदी अरब को भारी कीमत पर ये अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बेचे जा रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि पांचवीं पीढ़ी के इन खतरनाक लड़ाकू विमानों की सऊदी वायुसेना में एंट्री से पूरे अरब वर्ल्ड का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुई यह डिफेंस डील सिर्फ लड़ाकू विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सऊदी वायुसेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाने का एक व्यापक पैकेज है। इसमें 48 एफ-35 लाइटनिंग सेकंड फाइटर जेट्स, उनके लिए 49 बेहद शक्तिशाली प्रैट एंड व्हिटनी इंजन (एक स्पेयर के साथ), हाई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम, आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, उन्नत रडार, इलेक्ट्रानिक वारफेयर टूल्स और जरूरी स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं।

सौ फीसदी टैरिफ वाले रूस-ईरान प्रतिबंध बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर

वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट आफ 2026 पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। नया कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर सौ फीसदी तक आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का व्यापक अधिकार देता है। ब्रिटिश समाचार पत्र द गार्डियन के मुताबिक लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट आफ 2026 पर अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया है। इसी सप्ताह प्रतिनिधि सभा ने इसे 262-159 मतों से मंजूरी दी थी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य रूस की आर्थिक क्षमता को कमजोर करना और यूक्रेन युद्ध से जुड़े उसके संसाधनों पर दबाव बनाना है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर सौ प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है। जिसके दायरे में मुख्य रूप से भारत और चीन आ सकते हैं। यह कानून राष्ट्रपति को विशिष्ट परिस्थितियों में छूट देने का अधिकार भी देता है, जिसमें कांग्रेस को यह प्रमाणित करना शामिल है कि छूट राष्ट्रीय हित में है। यह कानून ईरान के ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंधों को भी अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाता है। यह विधेयक अगस्त में अमेरिकी सीनेट में 86-11 के बड़े अंतर से पारित हुआ था। इसके बाद इस सप्ताह प्रतिनिधि सभा ने भी इसे 262-159 मतों से मंजूरी दी। विधेयक का नाम इस प्रस्ताव के प्रमुख समर्थकों में शामिल रहे रिपब्लिकन नेता सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि नए कानून से रूस पर पहले से लागू प्रतिबंधों को और भी सख्त किया गया है। जिसके तहत रूस के सरकारी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, रक्षा क्षेत्र से जुड़े नेटवर्क और ऊर्जा परिवहन में इस्तेमाल होने वाले जहाजों पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। अमेरिका के इस कदम का असर भारत और चीन सहित वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। हालांकि भारत ने इस घटनाक्रम से पहले ही साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के मुताबिक अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा और किसी भी बाहरी दबाव में आए बिना उन देशों से तेल या ऊर्जा संसाधन खरीदना जारी रखेगा जहां से उसे सही कीमत पर मिलते हैं।

नेपाल के संविधान दिवस पर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दी बधाई

काठमांडू। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नेपाल के संविधान दिवस के अवसर पर बधाई संदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए विदेश मंत्री शिशिर खनाल के नाम का उल्लेख कर संविधान दिवस के अवसर पर बधाई दी। विदेश मंत्री जयशंकर ने लिखा, नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल सरकार तथा समस्त नेपाली जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने कहा, हम अपनी गहरी और स्थायी मित्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अमेरिका की विदेश नीति : चिनफिंग की यात्रा से पहले तिब्बत कार्ड खेल रहे ट्रंप

वाशिंगटन

अमेरिका वैश्विक मंच पर अपनी विदेश नीति के तहत जहां चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की आगामी अमेरिका यात्रा से पहले तिब्बत में मानवाधिकारों और दलाई लामा के साथ बातचीत को लेकर बीजिंग पर दबाव बना रहा है। चीनी राष्ट्रपति की यात्रा से पहले, इंटरनेशनल कैंपेन फार तिब्बत (आईसीटी) सहित कई तिब्बत समर्थक संगठनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 11वें पंचेन लामा की रिहाई का मुद्दा उठाने का आग्रह किया है। पंचेन लामा को दलाई लामा ने 14 मई 1995 को मान्यता दी थी, जिसके तीन दिन बाद वह लापता हो गए थे।

आईसीटी की अध्यक्ष तेनचो ग्यात्सो ने बताया कि अमेरिका की तिब्बत नीति तिब्बतन पालिसी एक्ट, 2002 और रिजाल्व तिब्बत एक्ट, 2024 जैसे कानूनों से निर्देशित होती है, जो चीन और तिब्बत के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के सार्थक बातचीत की वकालत करते हैं। ग्यात्सो ने ट्रंप से अपनी बैठक का उपयोग इस बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए चीन पर दबाव बनाने के लिए करने का आग्रह किया है, खासकर तब जब चीन का नया जातीय एकता एवं प्रगति कानून तिब्बती पहचान के लिए खतरा पैदा कर रहा है। कुल 29 मानवाधिकार संगठनों ने शी चिनफिंग को लिखे खुले पत्र में तिब्बतियों, उइगरों और अन्य समुदायों के खिलाफ चीन की अत्याचारी गतिविधियों की निंदा की है, जिनका उद्देश्य उनकी संस्कृति और पहचान को मिटाना है। उन्होंने शी से दलाई लामा के प्रतिनिधियों और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (जिसे तिब्बती लोगों का एकमात्र वैध लोकतांत्रिक प्रतिनिधि बताया गया) के साथ सार्थक बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की। इन संगठनों ने 11वें पंचेन लामा और अन्य राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई की भी अपील की है, और यदि उन्हें रिहा नहीं किया जाता, तो अमेरिकी अधिकारियों को उनसे स्वतंत्र रूप से मिलने की अनुमति देने की मांग की है।

इस अधिनियम के तहत, अमेरिकी विदेश विभाग तिब्बत के लिए एक विशेष समन्वयक की नियुक्ति करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य तिब्बती लोगों के लिए सार्थक स्वायत्तता और दलाई लामा के उत्तराधिकार के मुद्दे पर चीन पर दबाव बनाना होगा। अमेरिका ने तिब्बत में विदेशी राजनयिकों, पत्रकारों और नागरिकों के लिए निर्बाध पहुंच की भी मांग की है, जो चीन अक्सर प्रतिबंधित करता है। चीन ने इस अमेरिकी कदम की कड़ी निंदा की है, इसे अपने आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप बताया है और अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर और आगे न बढ़े। बीजिंग का मानना है कि तिब्बत उसके संप्रभु क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन का यह कदम आगामी उच्च-स्तरीय बैठकों में चीन पर अतिरिक्त राजनयिक और भू-राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।

चीन में हवा में उल्टी लटककर तेज दौड़ती है सस्पेंडेड मोनोरेल

बीजिंग

चीन के वुहान प्रांत में चलने वाली एक सस्पेंडेड मोनोरेल जमीन पर बिछी पटरी पर दौड़ने के बजाय ऊपर बने गाइडवे से नीचे की ओर लटकी रहती है। इस सस्पेंडेड मोनोरेल को 'ऑप्टिक्स वैली स्काईरेल और 'ऑप्टिक्स वैली फोटॉन के नाम से जाना जाता है। ट्रेन के अंदर बैठने वाले यात्रियों को कांच के फर्श और बड़ी खिड़कियों के जरिए नीचे का नजारा दिखाई देता है, जिससे सफर रोमांच और डर का अनोखा अनुभव बन जाता है।

झइसका डिजाइन पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इसमें ट्रैक जमीन के नीचे या सामान्य पिलर के ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर की तरफ बने एक मजबूत गाइडवे के रूप में तैयार किया गया है। ट्रेन का ऊपरी हिस्सा स्टील और कंक्रीट से बने सिंगल बीम से जुड़ा रहता है। बाहर से देखने पर ट्रेन हवा में उल्टी लटकी हुई नजर आती है, लेकिन इसका ढांचा विशेष रूप से इसी तरह के संचालन के लिए तैयार किया गया है। ट्रेन में रबर के पहियों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यात्रा के दौरान शोर कम होता है और संचालन अपेक्षाकृत सहज रहता है। फिलहाल इसमें दो डिब्बों का ट्रेन सेट चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 220 यात्री सफर कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार इसके डिब्बों की संख्या बढ़ाकर छह तक की जा सकती है।

इस ट्रेन की सबसे खास विशेषता इसका कांच का फर्श और बड़े पारदर्शी शीशे हैं। इनके कारण यात्रियों को करीब 270 डिग्री तक का दृश्य देखने का अनुभव मिलता है। ट्रेन जब ऊंचाई पर चलती है तो नीचे दिखाई देने वाला शहर और आसपास का इलाका सफर को किसी रोमांचक जॉय राइड जैसा बना देता है। कुछ यात्रियों के लिए यह अनुभव रोमांचक होता है, जबकि ऊंचाई से डरने वालों के लिए कांच के फर्श से नीचे देखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तकनीक के मामले में भी यह ट्रेन काफी आधुनिक है।

ट्रेन सेट बैटरी से संचालित होता है और इसे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था के तौर पर विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम डिजाइन गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, जबकि यात्रियों के साथ इसे करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति से चलाया जा रहा है। यह पूरी तरह स्वचालित और ड्राइवरलेस प्रणाली पर आधारित है।

ट्रेन के संचालन, गति नियंत्रण और स्टेशन पर दरवाजों के खुलने-बंद होने जैसी प्रक्रियाएं स्वचालित प्रणाली से नियंत्रित की जाती हैं। परियोजना के पहले चरण में करीब 10.5 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया गया है, जिस पर छह स्टेशन हैं। यह मार्ग जिउफेंग राष्ट्रीय वन पार्क के जिउफेंगशान से लोंगक्वानशान तक जाता है। कुछ स्टेशनों पर यात्रियों को अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से जुड़ने की सुविधा भी मिलती है। ट्रेन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलती है और यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 10 मिनट के अंतराल पर सेवा उपलब्ध कराई जाती है। हवा में लटकी यह ट्रेन चीन की आधुनिक परिवहन तकनीक का ऐसा उदाहरण है, जिसमें इंजीनियरिंग, स्वचालन और पर्यटन को एक साथ जोड़ा गया है।